

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।

(जी-3, राजमहल पैलेस रेजिडेंशियल एरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गौदाम जयपुर-302013)

(टैलीफैक्स-0141-2222403, ई-मेल-dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट www.lsgraj.org)

क्रमांक:-एफ.29/फायर/विविध/डीएलबी/18/1122-1365

दिनांक 14/3/19

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी
नगर निगम/परिषद/पालिकाएँ
समस्त राजस्थान

विषय:- फायर शुल्क एवं फायर सैस वसूली के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य की नगरीय निकायों में फायर शुल्क एवं फायर सैस की वसूली के संबंध में नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.110(7)नविवि/3/2009 पार्ट-II दिनांक 04.10.2013 में आंशिक संशोधन कर अधिसूचना क्रमांक प.18(13)नविवि/जयपुर/2016/दिनांक 07.03.2018 जारी की है उक्त अधिसूचना के बिन्दु संख्या 09 में 15 मीटर से अधिक ऊँचाई के बहुमंजिला भवनों के प्रस्तावित कुल गणना योग्य निर्मित क्षेत्र पर रु. 50/- वर्ग मीटर की दर से अग्निशमन शुल्क देय होगा। उक्त राशि आवेदक द्वारा स्थानीय निकाय में जमा कराई जावेगी एवं निर्माण अनुज्ञा देने वाली प्राधिकरण/न्यास में जमा राशि की रसीद प्रस्तुत की जावेगी। उपरोक्त वर्णित राशि के अलावा इस मद में अन्य कोई राशि नहीं ली जावेगी। भवन निर्माण पूर्ण होने पर कम्प्लीशन सर्टिफिकेट जारी करते समय स्थायी अग्निशमन अनुज्ञा प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा एवं इसके लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा। तत्पश्चात प्रति वर्ष अग्निशमन सुविधाओं की जांच व मॉक ड्रिल Empanelled फायर एक्सपर्ट से विकासकर्ता के स्तर पर कराई जावेगी, जिसका व्यय विकासकर्ता/रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (R.W.A.) के द्वारा वहन किया जावेगा। उपरोक्त वार्षिक मोक ड्रिल की दिनांक व समय की सूचना विकासकर्ता/ रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (R.W.A.) द्वारा संबंधित नगरीय निकाय/स्थानीय निकाय को दी जावेगी, ताकि अग्निशमन शाखा के अधिकारी/प्रतिनिधि मॉक ड्रिल के समय मौके पर उपलब्ध रहे।

उक्त राशि के व्यय के संबंध में कार्ययोजना तैयार करने हेतु नगरीय निकाय स्तर पर समिति का गठन किया जावेगा। राज्य सरकार द्वारा इस राशि का उपयोग करने हेतु पृथक से निर्देश संबंधित निकाय को दिये जा सकेंगे। अतः फायर शुल्क एवं फायर सैस वसूली के संबंध में उक्तानुसार कार्यवाही करें।

संलग्न:- आदेश/अधिसूचना की प्रति

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, अवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.10(7)नविवि/3/2009पार्ट-II

जयपुर, दिनांक -

4 OCT 2013

आदेश

नगरीय विकास विभाग के लिए गठित एम्पावरड समिति की 11वीं बैठक दिनांक 01.10.2013 के आईटम नं. 8 पर बहुमजिले भवनों में 60 मीटर से अधिक ऊंचाई अनज्ञेय किये जाने के संबंध में नीति तैयार करने का निर्णय लिया गया था। उक्त निर्णय की अनुपालना में अधिकतम ऊंचाई के भवनों के भवन मानचित्र अनुमोदन किये जाने के लिए अग्निशमन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से निम्नानुसार शुल्क लिये जाने का भवन विनियमों के अन्तर्गत प्रावधान किया जाता है -

राज्य के नगरीय क्षेत्रों में अग्निशमन की सुविधा उपलब्ध कराने/सुदृढीकरण की दृष्टि से निम्नानुसार शुल्क देय होगा :-

क्र. सं.	प्रस्तावित भवन की ऊंचाई	देय शुल्क (एफ.ए.आर. क्षेत्रफल पर प्रति वर्गमीटर)
1.	15 मीटर से अधिक परन्तु 40 मीटर तक	100 रुपये प्रति वर्गमीटर
2.	40 मीटर से अधिक परन्तु 60 मीटर तक	(क) 40 मीटर तक एफ.ए.आर. क्षेत्रफल पर 100 प्रति वर्गमीटर की दर से (ख) 40 मीटर से अधिक 60 मीटर तक ऊंचाई पर प्राप्त एफ.ए.आर. क्षेत्रफल पर 150 रुपये प्रति वर्गमीटर
3.	60 मीटर से अधिक	(क) 40 मीटर तक एफ.ए.आर. क्षेत्रफल पर 100 प्रति वर्गमीटर की दर से (ख) 40 मीटर से अधिक 60 मीटर तक ऊंचाई पर प्राप्त एफ.ए.आर. क्षेत्रफल पर 150 रुपये प्रति वर्गमीटर (ग) 60 मीटर से अधिक ऊंचाई पर प्राप्त एफ.ए.आर. क्षेत्रफल पर 200 रुपये प्रति वर्गमीटर

टिप्पणी :-

- (i) उक्त राशि भवन विनियमों के अन्तर्गत देय बैटरमेंट लेवी/अन्य शुल्कों के अतिरिक्त देय होगी।

44

- (ii) सभी नगरीय निकायों के स्तर पर उक्त राशि के लिए एक डेडिकेटेड फण्ड तैयार किया जायेगा, जो कि सामान्य से अतिरिक्त अकाउन्ट में जमा रखा जावेगा व इस राशि का व्यय संबंधित नगरीय निकाय के क्षेत्र में आवश्यकतानुसार अग्निशमन उपकरण/फायर टेन्डर आदि क्रय किये जाने तथा फायर एक्सपर्ट्स के माध्यम से बहुमंजिले भवनों में लगाये गये अग्निशमन उपकरणों आदि के वार्षिक निरीक्षण/परीक्षण किये जाने के लिए किया जायेगा। इस संबंध में राज्य/स्थानीय स्तर पर फायर एक्सपर्ट का पैनल तैयार कर बहुमंजिला भवनों में अग्निशमन सुविधाओं संबंधी प्रावधानों की भवन मानचित्र अनुमोदन, भवनों की पूर्णता पश्चात् अधिवास प्रमाण पत्र जारी किये जाने एवं समय-समय पर अग्निशमन सुविधाओं की जांच व Mock Drill में स्थानीय निकायों को तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगे।
- (iii) बहुमंजिला भवनों में अग्निशमन संबंधी नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित किये जाने की सम्पूर्ण जम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
- (iv) राशि के व्यय के संबंध में कार्य योजना तैयार करने हेतु संबंधित नगरीय निकाय स्तर पर निम्नानुसार समितियों का गठन किया जाता है :-

क.	प्राधिकरणों के लिए -	
	सचिव, संबंधित प्राधिकरण	- अध्यक्ष
	उप/वरिष्ठ नगर नियोजक बीपीसी	- सदस्य
	स्थानीय निकाय में अग्निशमन सेवा का वरिष्ठ अधिकारी	- सदस्य
	अध्यक्ष द्वारा नामांकित अधिशाषी अभियंता	- सदस्य सचिव
ख.	न्यासों के लिए -	
	सचिव, संबंधित न्यास	- अध्यक्ष
	उप/वरिष्ठ नगर नियोजक बीपीसी/अन्य प्राधिकृत अधिकारी	- सदस्य
	स्थानीय निकाय में अग्निशमन सेवा का वरिष्ठ अधिकारी	- सदस्य
	अध्यक्ष द्वारा नामांकित अधिशाषी अभियंता	- सदस्य सचिव
ग.	अन्य नगर निगमों/परिषदों/पालिकाओं के लिए -	
	मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी	- अध्यक्ष
	संबंधित निकाय	- अध्यक्ष
	उप/वरिष्ठ नगर नियोजक बीपीसी/अन्य प्राधिकृत अधिकारी	- सदस्य
	स्थानीय निकाय में अग्निशमन सेवा का वरिष्ठ अधिकारी	- सदस्य
	अध्यक्ष द्वारा नामांकित अधिशाषी अभियंता	- सदस्य सचिव

(गुरदयाल सिंह संघु)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
2. सहायक सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन स्वायत्त शासन, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।

45

4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगरीय निकायों को आवश्यक निर्देश उनके स्तर पर प्रदान किये जाने हेतु।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर/आबू जिला - सिरौही/भरतपुर/भिवाड़ी/भीलवाड़ा/वीकानेर/बांसवाड़ा/बाड़मेर/चित्तोड़गढ़/जैसलमेर/कोटा/पाली/सीकर/श्रीगंगानगर/सवाईमाधोपुर/उदयपुर।
8. गार्ड फाईल।


संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

0
रि
अ
अ
फ
र
-
ब
र

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक. प. 8(13)नविनि/जयपुर/2016

जयपुर, दिनांक **17 MAR 2018**


अधिसूचना

एकीकृत भवन विनियम-2017 राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन से लागू किये गये हैं। राजस्थान एकीकृत भवन विनियम-2017 के विनियम 7.1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात राजस्थान एकीकृत भवन विनियम-2017 के निम्न प्रावधानों को संशोधित/पुनर्स्थापित/अतिरिक्त जोड़ा जाता है:-

क्र.सं.	विनियम संख्या	संशोधित प्रावधान										
1	8.2	<p>तालिका 1 के नोट के बिन्दु संख्या 3 में निम्नानुसार जोड़ा जाता है :- जिन क्षेत्रों में आवासीय/व्यवसायिक आरक्षित दर निर्धारित नहीं है ऐसे क्षेत्रों में वहाँ की विभिन्न उपयोगों हेतु प्रचलित डीएलसी दर को आरक्षित दर मानते हुए अतिरिक्त बीएआर 200 राशि की गणना की जावेगी। मानक बी.ए.आर. से अधिक बी.ए.आर. प्रस्तावित किये जाने पर वटरमेट लेवी की दर आवासीय, सरथागत, होटल, मोटल एवं रिसोर्ट प्रयोजनार्थ आवासीय आरक्षित दर पर एवं वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ (होटल, मोटल एवं रिसोर्ट को छोड़कर)- व्यावसायिक आरक्षित दर पर (व्यावसायिक आरक्षित दर निर्धारित नहीं होने पर आवासीय आरक्षित दर का दो गुना)</p> <table border="0"> <tr> <td>1. 2.0 बी.ए.आर तक</td> <td>वटरमेट लेवी देय नहीं</td> </tr> <tr> <td>2. 2.0 से अधिक परन्तु 3.5 बी.ए.आर तक</td> <td>आरक्षित दर का 20 प्रतिशत</td> </tr> <tr> <td>3. 3.5 से अधिक परन्तु 5.0 बी.ए.आर तक</td> <td>आरक्षित दर का 25 प्रतिशत</td> </tr> <tr> <td>4. 5.0 से अधिक परन्तु 6.5 बी.ए.आर तक</td> <td>आरक्षित दर का 30 प्रतिशत</td> </tr> <tr> <td>5. 6.5 बी.ए.आर से अधिक</td> <td>आरक्षित दर का 35 प्रतिशत</td> </tr> </table> <p>उक्त दरों की गणना चरणबद्ध (Stage Wise) प्रक्रिया से की जावेगी।</p>	1. 2.0 बी.ए.आर तक	वटरमेट लेवी देय नहीं	2. 2.0 से अधिक परन्तु 3.5 बी.ए.आर तक	आरक्षित दर का 20 प्रतिशत	3. 3.5 से अधिक परन्तु 5.0 बी.ए.आर तक	आरक्षित दर का 25 प्रतिशत	4. 5.0 से अधिक परन्तु 6.5 बी.ए.आर तक	आरक्षित दर का 30 प्रतिशत	5. 6.5 बी.ए.आर से अधिक	आरक्षित दर का 35 प्रतिशत
1. 2.0 बी.ए.आर तक	वटरमेट लेवी देय नहीं											
2. 2.0 से अधिक परन्तु 3.5 बी.ए.आर तक	आरक्षित दर का 20 प्रतिशत											
3. 3.5 से अधिक परन्तु 5.0 बी.ए.आर तक	आरक्षित दर का 25 प्रतिशत											
4. 5.0 से अधिक परन्तु 6.5 बी.ए.आर तक	आरक्षित दर का 30 प्रतिशत											
5. 6.5 बी.ए.आर से अधिक	आरक्षित दर का 35 प्रतिशत											
2	8.2.1 (द) (vi)	<p>1000 वर्गमीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों में सार्वजनिक सुविधाएँ यथा सामुदायिक कक्ष, पुस्तकालय, क्लब, जिम, सोसायटी कार्यालय, कॉमन स्टोर, कॉमन टैंगलेट आदि हेतु सिटिल प्लॉर पर सिटिल प्लॉर के क्षेत्रफल का न्यूनतम 5 प्रतिशत रखा जाना आवश्यक होगा तथा सिटिल प्लॉर पर अनुज्ञेय व्यवसायिक उपयोग सार्वजनिक सुविधाएँ हेतु अधिकतम 30 प्रतिशत तक क्षेत्र अनुज्ञेय होगा और सिटिल प्लॉर प्रस्तावित नहीं है तो उक्त सार्वजनिक सुविधाएँ किसी भी अन्य तल पर अनुज्ञेय की जा सकेंगी। सार्वजनिक उपयोग हेतु अनुज्ञेय किये गये क्षेत्र का कंपल भवन निवासियों की सुविधाओं के लिए ही आरक्षित रखा जावेगा, इसका विकल्प नहीं किया जा सकेगा तथा विकसकर्ता द्वारा उक्त सुविधा क्षेत्र विकसित कर इसको रख रखाव हेतु रजिस्ट्रार वेलफेयर एंजिनियरिंग (R.W.A.) को हस्तान्तरित करना होगा।</p>										
3	8.2.1(द) (vii)	विनियम 8.2.1(द) (vii) में लिखित "भवन विनियम 2015 को" शब्दावली जगह हटा										
4	8.2.1 (द) (viii) (अ) (i)	<p>फार्म हाउस (i) फार्म हाउस (अर्थात् आवासीय/व्यवसायिक) /वाणिज्यिक वास्तु निर्माण विनियम 2017 में अनुसूचित होगा। (ii) फार्म का न्यूनतम क्षेत्रफल 2500 वर्गमीटर आवश्यक है। (iii) फार्म का क्षेत्रफल 2500 वर्गमीटर पर अधिक हो तो न्यूनतम क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर का होगा जो स्थिति में विनाशिक आदर कक्षाक प 3(4)2008 में 3.2008-पार्ट दिनांक 12.08.2015 के अनुसार रखा जाना अनिवार्य होगा।</p>										
5	8.2.2 (iv)	विनियम संख्या 8.2.2 (iv) में बिन्दु संख्या (iv) निम्नानुसार जोड़ा जाता है - (iv) आवासीय भवन निर्माण पर अनुज्ञेय होगा।										
6	8.2.2(घ) (i)	<p>विनियम 8.2.2(घ) (i) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है - (i) सिटिल प्लॉर सिटिल प्लॉर का न्यूनतम क्षेत्रफल उक्त संशोधित भवन पर निर्माण हेतु न्यूनतम 5 प्रतिशत क्षेत्रफल 2500 वर्गमीटर होगा।</p>										

7	8.2.2 (ज)	नोट (iii) के पश्चात नोट (iv) जोड़ा जाता है। (iv) पेट्रोल पम्प भूखण्ड राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/मुख्य जिला सड़क/अन्य जिला सड़क (NH/SH/MDR/ODR) पर स्थित होने की स्थिति में संबंधित ऐजन्सी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/पी.डब्ल्यू.डी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करना अनिवार्य है।
8	8.2.3 (iv)	संस्थागत बहुमंजिले भवन 1000 वर्गमीटर अथवा उससे अधिक बड़े भूखण्डों पर तथा सड़क की चौड़ाई बड़े शहरों हेतु 18 मीटर व लघु व मध्यम शहरों हेतु 15 मीटर होने पर ही देय होंगे।
	8.3 (i)	बहुमंजिला भवन न्यूनतम 1000 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड एवं आवासीय एवं संस्थागत उपयोग हेतु बड़े शहरों में न्यूनतम 18 मीटर, मध्यम/लघु शहरों में 15 मीटर तथा वाणिज्यिक उपयोग हेतु बड़े शहरों में न्यूनतम 24 मीटर व मध्यम/लघु शहरों में 18 मीटर चौड़ी सड़क लेने ही अनुज्ञेय होंगे।
9	8.3.1(i)	15 मीटर से अधिक ऊंचाई के बहुमंजिला भवनों के प्रस्तावित कुल गणना योग्य निर्मित क्षेत्र पर रु 50/- वर्गमीटर की दर से अग्निशमन शुल्क देय होगा। उक्त राशि आवेदक द्वारा स्थानीय निकाय में जमा कराई जावेगी एवं निर्माण अनुज्ञा देने वाली प्राधिकरण/न्याय में जमा राशि की रसीद प्रस्तुत की जावेगी।
	8.3.1(ii)	8.3.1(i) में वर्णित राशि के अलावा इस मद में अन्य कोई राशि नहीं ली जावेगी। भवन निर्माण पूर्ण होने पर कम्प्लीशन सर्टिफिकेट जारी करते समय स्थायी अग्निशमन अनुज्ञा प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा एवं इसके लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा। तत्पश्चात प्रति वर्ष अग्निशमन सुविधाओं की जाँच व मॉक ड्रिल Empanelled फायर एक्सपर्ट से विकासकर्ता के स्तर पर कराई जावेगी जिसका व्यय विकासकर्ता/ रेजीडेंट वेल्फेयर एसोसिएशन (R.W.A.) के द्वारा वहन किया जावेगा। उपरोक्त वार्षिक मॉक ड्रिल की दिनांक व समय की सूचना विकासकर्ता/ रेजीडेंट वेल्फेयर एसोसिएशन (R.W.A.) द्वारा संबंधित नगरीय निकाय/स्थानीय निकाय को दी जावेगी, ताकि अग्निशमन शाखा के अधिकारी/प्रतिनिधि मॉक ड्रिल के समय मौके पर उपलब्ध रहे।
	8.3.1(iii)	इस राशि के व्यय के संबंध में कार्ययोजना तैयार करने हेतु नगरीय निकाय स्तर पर समिति का गठन किया जावेगा।
	8.3.1(iv)	राज्य सरकार द्वारा इस राशि का उपयोग करने हेतु पृथक से निर्देश संबंधित निकाय को दिये जा सकेंगे।
10	8.7 (iii)	विनियम 8.7 (iii) में उल्लिखित "न्यूनतम अग्र सैटबैक तालिका 1 के अनुसार ही रखा जावेगा" हटाया जाता है।
11	8.7 (Xiii)	विनियम 8.7 (Xiii) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है -अर्थात्, साईड व बैक सैटबैक में मैकेनिकल पार्किंग अनुज्ञेय नहीं होगी। मैकेनिकल पार्किंग नियमानुसार सैटबैक छोड़ने के पश्चात भू-तल के शेष भाग में दी जा सकेगी। -
12	8.11.1	"जिन नगरीय क्षेत्रों में जल संकट क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में जहाँ जल संरक्षण संरचनाएँ कठोर अनिवार्य नहीं होंगी। संबंधित प्राधिकरण/न्याय को वकालत में इस संबंध में आवश्यक प्रस्ताव पारित किये जाने के पश्चात उपरोक्त अनिवार्यता नहीं रहेगी एवं ऐसे प्रकरणों में तालिका 11 में इन वाटर हारबोस्टिंग हेतु सालाना की कॉलम 8 में दर्शायी गई अमानत राशि जमा नहीं कराई जावेगी।
13	8.11.3	प्रत्येक 100 वर्गमी क्षेत्रफल (गार्ड) द्वारा की स्थिति में 50 वर्गमी क्षेत्रफल के लिए) के लिए कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में बड़े वृक्ष जो छ: मी या इससे अधिक ऊंचाई वहन कर सकेंगे ही लगाने होंगे। इस प्रावधान को अनुपालना नहीं करने पर 1000/- प्रति वृक्ष की दर से राशि स्थानीय निकाय में जमा करानी होगी, जिस राशि का उपयोग वृक्ष भूखण्ड पर वृक्ष लगाने में किया जायेगा।
14	8.11.4	टीन विहडिंग के निर्माण विनियमन पर मानक गणना योग्य निर्मित क्षेत्रफल को प्रतिवर्त 2.5 प्रतिशत (0.025) गणना योग्य विहडिंग क्षेत्र निशुल्क किया जाएगा। जहाँ जहाँ राशि की प्रति विनियमन पर देय होगी।
15	8.12.3.2 (iv) (3)	विनियम 8.12.3.2 (iv) (3) में "कक्षा 2/कक्षा भवन निर्माण संहिता (इंजीनियरिंग) 2007 के खंड 1 पर "वर्तमान में प्रचलित नवम्बर संशोधन भवन निर्माण संहिता (इंजीनियरिंग) प्रतिस्थापित किया जाता है।
16	8.16 (vi)	विनियम 8.16 (vi) से उल्लिखित "बैक पार्किंग करना व कोरर पार्किंग हेतु प्रस्ताव" के स्थान पर "कक्षा पार्किंग हेतु प्रस्ताव" संशोधित किया जाता है।

17	14.11	अनुसूची 2 का बिन्दु संख्या 11, "यदि निर्धारित अवाधे क पश्चात नवीनीकरण कराया जाता है तो क्रम संख्या 1 के अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क तथा क्रम संख्या 2-3 के अनुसार मानचित्र जॉब एवं अनुमोदन शुल्क का 20 प्रतिशत"।
18	14.15 (iii)	विनियम संख्या 14.15 (iii) में उल्लेखित "बिन्दु संख्या 14.14 (i) व (ii)" के स्थान पर "बिन्दु संख्या 14.15 (i) व (ii)" संशोधित किया जाता है।


 09/3/18
 (राजेन्द्र सिंह शेखावत)
 संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्थायत्त शासन विभाग।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
6. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
7. सलाहकार (नगर नियोजन), नगरीय विकास विभाग।
8. सचिव, नगर विकास न्यास, समरत।
9. अधीक्षक, राजकीय केंद्रीय मुद्रणालय जयपुर को मय सी.डी. भेजकर लेख है कि इस अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कर प्रकाशित अंक की एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करे।
10. अतिरिक्त उपाय शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. रचित पत्रावली।


 06/3/18
 संयुक्त शासन सचिव-प्रथम